



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 10 नवम्बर, 2003/19 कार्तिक, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अगिसूचना

शिमला-171 002, 13 अक्तूबर, 2003

संख्या एफ0डी0एस0-वी(3)-2/96-लूज-I—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस सरकार की अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस-ए(3)-4/82-III, तारीख 20 अप्रैल, 1988 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 मई, 1988 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवा संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 में नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थातः—

“(1) हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन, भत्ते व अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने तथा अन्य सदस्य यदि पूर्ण-कालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो

तो एक हजार पांच सौ रुपए (1500/- रुपए) संचित मानदेय प्रतिमाह और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो तो छः सौ रुपए (600/- रुपए) प्रति दिन प्रति बैठक प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु सदस्य सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई पेंशन का हकदार होगा किन्तु मानदेय और पेंशन उस द्वारा आहरण किए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा” ।

आदेश द्वारा,

बी० एस० चौहान
सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-B(3)-2/96-Loose-I, dated 13-10-2003 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th October, 2003

No. FDS-B(3)-2/96-Loose-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988, notified *vide* this Government Notification No. FDS-A(3)-4/82-III, dated the 20th April, 1988 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 14th May, 1988, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (5th Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of rule 13.*—In rule 13 of the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) The President of the State Commission shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to a sitting Judge of the High Court and Other members, if appointed on whole time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 1500/- per month or if appointed on Part time basis a consolidated honorarium of Rs. 600/- per day for sitting shall be paid:

Provided that a Member shall be eligible to any pension granted him by the Government or any authority but honorarium plus pension shall not exceed the last pay drawn by him”.

By order,

B. S. CHAUHAN,
Secretary.